

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 705] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2016/चैत्र 1, 1938 No. 705] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2016/CHAITRA 1, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2016

का.आ. 1167(अ).—िनम्निलिखित अधिसूचना का प्रारुप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए, प्रकाशित की जाती है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

रामनगर वन्यजीव अभयारण्य जम्मू शहर के उत्तरी भाग की ओर स्थित है । रामनगर वन्यजीव अभयारण्य 12.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है । अभयारण्य की सीमाएं नीचे दिए अनुसार है ;

(1)

उत्तर - करेनवाली रक्ख

पूर्व - तवी नदी और खानपुर गांव

दक्षिण - जम्मू शहर

1406 GI/2016

पश्चिम - जानीपुरा और शांगन की बस्तियां

और, इस अभयारण्य में वनस्पति और जीव जन्तु की समृद्ध जैविक महत्व का प्रतिनिधित्व है ;

और, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य बड़ी संख्या के शाकभक्षी और पक्षी जीव-जन्तु के प्रचुर जैव विविधता के वास के लिए जाना जाता है। मुख्य प्रजातियों में सामान्य भारतीय तेंदुआ, रेसुस लघु पुच्छ वानर, मुंजक, बनैला सूअर, नीलगाय, साही, रेड जंगल फाउल, मटरमुर्गा, अजगर, रुसेल वाइपर (कोबरा) तीतर और अन्य पक्षी प्रजातियां सम्मिलित है। वन्यजीव संरक्षण दृष्टिकोण के महत्व के अलावा, यह क्षेत्र पारिस्थितिक के लिए जम्मू शहर के निकटता में बहुत महत्वपूर्ण है और यह तवी नदी से जल ग्रहण भी करता है;

और, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के अंर्तगत समूह 9 (सी-1) में उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन आते है । यह क्षेत्र सघन मिश्रित झाड़ी वन के साथ प्रासंगिक चीर (पीनस रॉक्सबरघी) वृक्षों से ढ़का हुआ है । इस क्षेत्र में आिकया मोडेस्टा (फुल्लई) सर्वाधिक है । अन्य सामान्य प्रजातियों में अकािकया केचु (खैर), बॉम्बेक्स सेइबा, (सिल्क कॉटन ट्री), कैस्सिया फिसटुला (अमलतास), अकािकया अराबिका (बौल), डलबेरगिया सिस्सु (शिशम), मल्लोटस फेल्लीपीनानसिस, और ग्रेविया आिएटवा हैं और कुछ अन्य प्रजातियां आधाटोडा वािसका, अदिनिया कार्डिफोलिया (हल्दु), एगले मारमेलोस (बेल), अगेरटम कोिनीज़ोइडेस (गोट वीड), अलिविज़िया लब्बेक (सीरीस), बौहीिनीया परपरिया (खनवाल), कैलोट्रोपिस प्रोसेरा (आक), कैसकटा रेफ्लेक्सा (डोड्डर) टूना सिलिआटा (टून) हैं;

और, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू-कश्मीर राज्य में रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1850.43 मीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर राज्य में रामनगर वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

- 1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1850.43 मीटर के क्षेत्र में होगा पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई ग्राम नहीं है, रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ जीपीएस निर्देशांक बिन्दु **उपाबंध ।** के रूप में उपाबद्ध है।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का सीमा के ब्यौरों तथा अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र **उपाबंध** ॥ के रूप में उपाबद्ध है।
- 2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
 - (2) आचंलिक महायोजना का अनुमोदन राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- (3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति जैसा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है और सुसंगत केन्द्रीय और राज्य विधियों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुरूप भी तैयार की जाएगी।
- (4) आंचलिक महायोजना सभी संबद्ध राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--
 - (i) पर्यावरण ;
 - (ii) वन ;
 - (iii) नगर विकास ;

- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई;
- (x) लोक निर्माण विभाग।
- (5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी।
- (6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।
- (7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।
- (8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे कि स्थानीय समुदायों के पारिस्थितिक जन्य विकास और जीविका को सुनिश्चित किया जा सके।
- (9) जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार, उसकी अधिकारता के अधीन आने वाले क्षेत्र के लिए पृथक आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।
- **3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-
- (1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं. 10, 21, 29, 33 और 34 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात्:-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ करना ;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं सम्मिलित हैं; और
- (v) वर्षा जल संचय ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

- (2) प्राकृतिक जल स्रोतों -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे।
- (3) **पर्यटन** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी।
- (ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार की जाएगी ।
 - (ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा:
 - (ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा।

- (iii) आंचिलक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा।
- (4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा।

- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।
- (6) **ध्विन प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्विन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।
- (8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।
- (9) ठोस अपशिष्ट ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -
 - (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
 - (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
 - (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा;
 - (iv) अकार्बिनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।
- (10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (11) **यानीय परिवहन** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।
- (12) औद्योगिक इकाईयां (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- (ख) जल, वायु, मृदा, ध्विन प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।
- 4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी				
(1)	(2)	(3)				
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप						
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां प्रतिषिद्ध हैं, सिवाय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के नहीं होंगी, जिसके अंतर्गत गृहों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए मिट्टी की खुदाई और व्यक्तिगत उपभोग के लिए गृहों के निर्माण के लिए देशी टाइलों या ईंटों का संनिर्माण भी है; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख				
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा। पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का				
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा । लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।				
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।				
(5)	नई बृहत ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।				
(6)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।				
(7)	प्लास्टिक थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।				
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।				
(9)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्नाव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।				
	वि	नियमित क्रियाकलाप				
(10)	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर नए वाणिज्यक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना को सिवाए पारिस्थितिक के अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के लिए अस्थायी आवास के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि 1 किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के दिशा-निर्देश के अनुरूप होंगे।				
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय व्यक्तियों को उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उपपैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, को करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। (ख) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों के अनुसार, यदि कोई हों तो, सक्षम प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से न्यूनतम रखा जाएगा।				

	T	
		(ग) एक किलोमीटर से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सद्भावपूर्वक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण और अन्य संनिर्माण
		क्रियाकलापों को महायोजना के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
		(घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के
		अनुसार होंगे।
(12)	े टेन्चिंग ग्राउंड।	नए ट्रेन्चिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है । पुराने ट्रेन्चिंग ग्राउंड को लागू
(12)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।
(13)	प्राकृतिक जल निकायों में बहिर्स्नाव और ठोस	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	अपशिष्ट का निस्सारण ।	~
(14)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	ध्वनि प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(16)	भूमिगत जल का निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी
		या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी ।
		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन
		बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए
		विवरण का अनुसरण किया जाएगा ।
(18)	प्रवासी चारवाहे।	लागू विधियों और आंचलिक महायोजना के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	विद्यमान स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	विद्युत लाइनों का इन्सुलेशन।	भूमिगत केबल डालने का संवर्धन किया जाएगा । सभी विद्यमान विद्युत
		लाइनें जो पारिस्थितिक संवेदी जोन से होकर गुजरती हैं, को आंचलिक
		महायोजना के अधीन विहित समय-सूची में पर्याप्त रूप से इन्सुलेट किया
		जाएगा ।
(21)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(22)	्रेट होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड	ाण्या विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
	लगाना ।	वन्यजीव के मुक्त संचलन को अनुज्ञात करने के लिए पारिस्थितिक संवेदी
		जोन के भीतर होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी परिसंपत्तियों में
		कांटेदार से बाड़ नहीं लगाएंगे और कोई भी बाड़ एक मीटर से ऊंची नहीं
		होगी । कोई विद्यमान बाड़, जो इस उपदर्श का अनुपालन नहीं करती है, को
		आंचलिक महायोजना में वर्णित समय-सीमा के अनुसार उपांतरित किया
		जाएगा ।
(23)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	उपयोग, जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है।	
(25)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(28)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	सिवाय आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात के किसी संनिर्माण क्रियाकलाप को एक से दस से अधिक ढाल वाली पहाड़ियों पर और किसी
		कियाकलाप की एक स दस स आधक ढाल वाला पहााड़या पर आर किसा नदी और प्राकृतिक नाले से लगभग 100 मीटर तक अनुज्ञात नहीं किया
		जाएगा ।
(29)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा
		उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से
		अद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि यो कृषि आद्यारित देशीय माल स औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत
		प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञात किया जाएगा ।

	संवर्धित क्रियाकलाप					
(30)		सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।				
	और बागबानी पद्धतियों के साथ डेयरियां,					
	पशुपालन और मत्स्य पालन।					
(31)	जैविक कृषि ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।				
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।				
	को ग्रहण करना ।					
(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।				
	कारीगर आदि भी हैं।					
(34)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।				
(35)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।				

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात :-

(ক)	कलेक्टर, जम्मू	अध्यक्ष
(ख)	जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य
(ग)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
(ঘ)	प्रादेशिक अधिकारी, जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
(ङ)	प्रभागीय वन अधिकारी –वन्यजीव प्रबंधक, जम्मू	सदस्य-सचिव

6. निर्देश निबंधन -

- (1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।
- (2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।
- (3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।
- (5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्घ विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

- (7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।
- 6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे
- 7. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/184/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

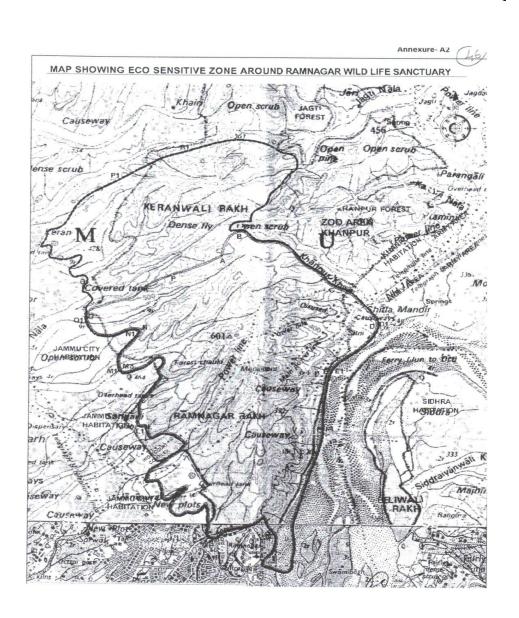
उपाबंध – ।

रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

豖.	अभयारण्य के	बिन्दु	पारिस्थितिक संवेदी	भू-	निर्देशांक	टिप्पणी
सं.	संबंध में सीमाओं की दिशा		जोन से संरक्षित क्षेत्र की सीमा तक की दूरी मीटर में	यक्षांश	देशांतर	
1.	उत्तर	ए1	अधिकतम दूरी=	ਤ 32⁰ 48'	पू 74º 51'	थाथेर ग्राम के चारों ओर का क्षेत्र
			1850 मीटर	11.67"	32.70"	
		बी1	न्यूनतम दूरी =	उ 32⁰ 47′	पू 74º 52'	
			00 मीटर मीटर	31.15"	5.77"	
2.	उत्तर पूर्व	सी1	अधिकतम दूरी =	ਤ 32º 47'	पू 74º 52'	खानपुर जेडीए कालोनी एवं
			00 मीटर	1.98"	56.89"	पर्यावास के चारों ओर का क्षेत्र
		डी1	न्यूनतम दूरी =	उ 32⁰ 46′	पू 74º 53'	
			758 मीटर	17.93"	42.28"	
3.	पूर्व	ई1	अधिकतम दूरी =	ਤ 32º 46'	पू 74º 53'	तवी नदी एवं सिधरा ग्राम
			1110 मीटर	10.35"	38.43"	
		एफ1	न्यूनतम दूरी =	ਤ 32º 45'	पू 74º 53'	
			1085 मीटर	44.30	33.91"	
4.	दक्षिण पूर्व	जी1	न्यूनतम दूरी =	ਤ 32⁰ 44′	पू 74º 53'	तवी नदी एवं जम्मू शहर नगर
			1293 मीटर	56.49"	22.24"	पालिका क्षेत्र पहले प्रजनन के लिए विकसित है ।
		एच1	अधिकतम दूरी =	उ 32º 44'	पू 74 º 53'	144000 61
			1472 मीटर	13.64"	23.97"	
5.	दक्षिण	आई1	अधिकतम दूरी =	उ 32⁰ 45'	पू 74º 52'	जम्मू शहर नगर पालिका क्षेत्र
			00 मीटर	00.22"	16.13"	पहले प्रजनन के लिए विकसित है ।
		जे1	न्यूनतम दूरी =	उ 32⁰ 44'	पू 74º 51'	
			00 मीटर	50.42"	47.08"	
6.	दक्षिण पश्चिम	के 1	अधिकतम दूरी =	ਤ 32º 45'	पू 74º 51'	जम्मू शहर नगर पालिका क्षेत्र
			00 मीटर	20.06"	13.26"	पहले प्रजनन के लिए विकसित है ।
		एल1	न्यूनतम दूरी =	ਤ 32º 45'	पू 74º 51'	
			00 मीटर	48.74"	10.85"	

7.	पश्चिम	एम1	अधिकतम दूरी =	ਤ 320 46′	पू 74º 51'	जम्मू शहर नगर पालिका क्षेत्र
			00 मीटर	19.70"	04.73''	पहले प्रजनन के लिए विकसित है ।
		एन1	न्यूनतम दूरी = 00	ਤ 32º 48'	पू 74 º 51'	
			मीटर	41.94"	16.41"	
8.	उत्तर पश्चिम	ओ1	न्यूनतम दूरी= 00	ਤ 32⁰ 46′	पू 74º 50'	जम्मू शहर नगर पालिका क्षेत्र
			मीटर	45.79"	42.80''	पहले प्रजनन के लिए विकसित है एवं केरन पर्यावासः

उपाबंध – ।। रामनगर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अक्षांश और देशांतर सहित मानचित्र



रामनगर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

क्र. सं.	अभयारण्य के संबंध में	बिन्दु	भू-ि	नेर्देशांक	टिप्पणी
	सीमाओं की दिशा		अक्षांश	देशांतर	
1.		ए	ਤ 32º 47' 18.37''	पू 74º 51' 57.16''	वन क्षेत्र के कूप सं. 4 के
	उत्तर	बी	उ 32⁰ 47′ 31.15″	पू 740 52' 5.77''	चारों ओर के क्षेत्र
2.		सी	ਤ 32⁰ 47' 1.98"	पू 74º 52' 56.89"	खानपुर, खानपुर पर्यावास
	उत्तर पूर्व	डी	उ 32º 46' 38.87''	पू 74º 53' 25.04"	- एवं आर्मी क्षेत्र के ज़ू क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र
3.		ई	ਤ 32º 46' 16.36"	पू 74º 52' 58.36"	तवी नदी एवं सिधारा
	पूर्व	एफ	उ 32º 45' 42.62''	पू 74º 52' 50.98"	- ग्राम का चारों ओर का क्षेत्र
4.		जी	ਤ 32⁰ 44′ 52.03″	पू 74º 52' 31.55"	तवी नदी एवं जम्मू शहर नगरपालिका क्षेत्र के चारों
	दक्षिण पूर्व	एच	उ 32º 44' 37.02"	पू 74º 52' 29.65"	न नगरपालिका क्षेत्र के चारा ओर का क्षेत्र
5.	दक्षिण	आई	ਤ 32⁰ 45′ 00.22″	पू 74º 52' 16.13"	जम्मू शहर नगरपालिका
	दाक्षण	जे	उ 32º 44' 50.42"	पू 74º 51' 47.08"	क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र
6.	दक्षिण पश्चिम	के	ਤ 32⁰ 45′ 20.06″	पू 74º 51' 13.26"	जम्मू शहर नगरपालिका
	दालण पाश्चम	एल	ਤ 32º 45' 48.74"	पू 74º 51' 10.85"	- क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र
7.	पश्चिम	एम	ਤ 32⁰ 46′ 19.70″	पू 74º 51' 04.73"	जम्मू शहर नगरपालिका
	पश्चिम	एन	उ 32º 48' 41.94"	पू 74º 51' 16.41"	- क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र
8.	उत्तर पश्चिम	ओ	ਤ 32º 46' 45.79"	पू 74º 50' 42.80"	जम्मू शहर नगर पालिका क्षेत्र पहले प्रजनन के लिए विकसित है एवं केरन पर्यावास।

उपाबंध – III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति-की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

- 1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
- 2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
- 3. आंचलिक महयोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
- 4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश ईआईए के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सारांश।
- 6. ब्यौरों को उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
- 7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
- 8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2016

S.O. 1167(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

Whereas, the Ramnagar Wildlife Sanctuary located on the Northern side of Jammu city. The Ramnagar Wildlife Sanctuary covers an area of 12.75 square kilometres. The boundaries of the sanctuary are as under:

North - Keranwali Rakh

East – River Tawi and Khanpur village

South – Jammu city

West - Settlements of Janipura and Shangan

And whereas, the flora and fauna represent rich biological significance of this sanctuary;

And whereas, the Ramnagar Wildlife Sanctuary is known for habitat of large number of herbivores and rich biodiversity of avifauna. The principal species include Common Indian Leopard, Rhesus Macaque, Barking Deer, Wild Boar, Nilgai, Porcupine, Red Jungle foul, Pea Fowl, Python, Russel Viper (Cobra) Partridges and other avian species. Besides being important from wildlife conservation point of view, this area is ecologically very important being in the close proximity of Jammu city and it also forms catchment of River Tawi;

The Ramnagar Wildlife Sanctuary area falls under Group 9 (C-1) Northern Dry Mixed Decidous Forest. The area is covered by dense mixed scrub forest with occasional Chir (Pinus roxburghii) trees. Acacia modesta (Phullai) predominated the area. Other common species are Acacia catechu (Khair), Bombax ceiba (Silk cotton tree), Cassia fistula (Amaltas), Acacia arabica (Baul), Dalbergia sissoo (Shisham), Mallotus phellipinensis, and Grewia optiva and few other species are Adhatoda vasica, Adinia cardifolia (Haldu), Aegle marmelos (Bel), Ageratum conyzoides (Goat Weed), Albizia labbeck (Siris), Bauhinia purpuria (Khanwal), Calotropis procera (Aak), Cascuta reflexa (Dodder), Toona ciliata (Toon);

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Ramnagar Wildlife Sanctuary as Eco-Sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area with an extent up to 1850.43 meters around the boundary of Ramnagar Wildlife Sanctuary in the State of Jammu and Kashmir as the Ramnagar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

- **1.** Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is 1850.43 meter around the Ramnagar Wildlife Sanctuary. There is no village falling in the in Eco-Sensitive Zone area. The Global Positioning System Co-ordinates of points along the boundary of Ramnagar Wildlife Sanctuary is appended as Annexure-I.
- (2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as Annexure-II.
- **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.
 - (2) The Zonal Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.
 - (3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-
 - (i) Environment,
 - (ii) Forest,
 - (iii) Urban Development,
 - (iv) Tourism,
 - (v) Municipal,
 - (vi) Revenue,
 - (vii) Agriculture,
 - (viii) Jammu and Kashmir State Pollution Control Board,
 - (ix) Irrigation,
 - (x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

- (5) The Zonal Master Plan shall not impose any restrictions on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.
- (7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.
- (8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (9) The Government of Jammu and Kashmir shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.
- 3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-
- (1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 21, 29, 33 and 34 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

- (2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.
- (b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Jammu and Kashmir in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government of Jammu and Kashmir.
- (c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Ramnagar Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that, beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in predefined and designated area for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

- (4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Jammu & Kashmir State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Jammu and Kashmir State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.
 - (9) Solid wastes. Disposal of solid wastes shall be as under:-
 - (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;
 - (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-bio-degradable components;
 - (iii) the bio-degradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
 - (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Ecosensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.
- (b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.
- 4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No	. Activity	Remarks		
(1)	(2)	(3)		
		Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.		
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.		
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.		
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
7.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
9.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.		
	•	Regulated activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Ecofriendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Ecosensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities would in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.		
11.	Construction activities.	 (a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3; (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone construction for bone fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan; 		

		(d) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
12.	Trenching ground.	Establishing of new trenching ground is prohibited. Old trenching grounds are to be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	 (a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder; (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers.	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments.	Regulated under applicable laws.
20.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling. All existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
23.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
24.	Commercial use of natural water resource including ground water harvesting.	Regulated under applicable laws.
25.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Sign board and hoardings.	Regulated under applicable laws.
28.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted by under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
29.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
20		Permitted activities
30.	On going agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Shall be actively promoted.

31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
34.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.

- **5. Monitoring Committee.-** The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-
- (a) Collector, Jammu Chairman
- (b) An expert in the area of ecology and environment Member to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir for a period of one year, in each case
- (c) One representatives of Non-Governmental Organisation Member working in the field of environment including heritage conservation to be nominated by the Government of Jammu and Kashmir for a period of one year.
- (d) Regional Officer, Jammu and Kashmir State Pollution Control Board Member
- (e) Divisional Forest Officer cum Wildlife Warden, Jammu Member-Secretary
- **6. Terms of Reference.**—(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
- (2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per pro-forma given in Annexure III.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

- 7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
- 8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/184/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

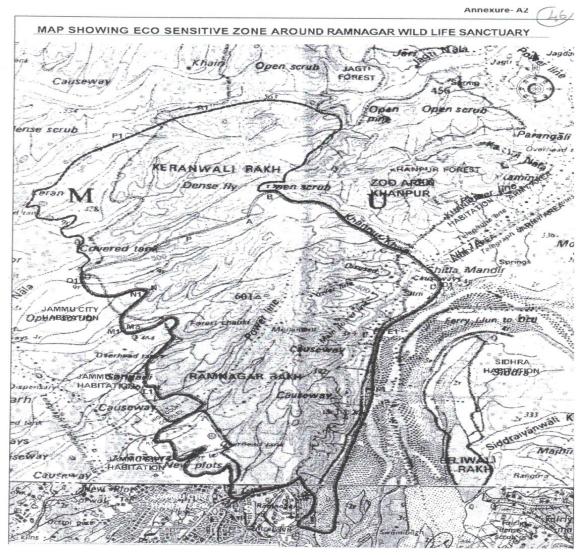
Annexure-I

TABLE SHOWING GEO-COORDINATES OF BOUNDARY OF ECO-SENSITRIVE ZONE AROUND RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY

S.	Direction w.r. t	Point	Distance in	Geo-C	Coordinates	Remarks
No	boundaries of the sanctuary		meters of ESZ from boundary of PA	Latitude	Longitude	
1	North	A1	Max. Distance= 1850 mtrs	N 32 ⁰ 48' 11.67''	E 74 ⁰ 51' 32.70''	Area surrounded by Thather village
		B1	Min. Distance = 00 mtrs	N 32 ⁰ 47' 31.15''	E 74 ⁰ 52' 5.77''	
2	North East	C1	Max. Distance = 00 mtrs	N 32 ⁰ 47' 1.98''	E 74 ⁰ 52' 56.89''	Area surrounded by Khanpur JDA colony
		D1	Min. Distance = 758 mtrs	N 32 ⁰ 46' 17.93''	E 74 ⁰ 53' 42.28''	and habitation.
3	East	E1	Max. Distance = 1110 mtrs	N 32 ⁰ 46' 10.35''	E 74 ⁰ 53' 38.43''	River Tawi and Sidhra village
		F1	Min. Distance = 1085 mtrs	N 32 ⁰ 45' 44.30	E 74 ⁰ 53' 33.91''	
4	South East	G1	Min. Distance = 1293 mtrs	N 32 ⁰ 44' 56.49''	E 74 ⁰ 53' 22.24''	River Tawi and Jammu city
		Н1	Max. Distance = 1472 mtrs	N 32 ⁰ 44' 13.64''	E 74 ⁰ 53' 23.97''	municipal area already developed from generations.
5	South	I1	Max. Distance = 00 mtrs	N 32 ⁰ 45' 00.22''	E 74 ⁰ 52' 16.13''	Jammu city municipal area
		J1	Min. Distance = 00 mtrs	N 32 ⁰ 44' 50.42''	E 74 ⁰ 51' 47.08''	already developed from generations.
6	South West	K1	Max. Distance = 00 mtrs	N 32 ⁰ 45' 20.06''	E 74 ⁰ 51' 13.26''	do
		L1	Min. Distance = 00 mtrs	N 32 ⁰ 45' 48.74''	E 74 ⁰ 51' 10.85''	
7	West	M1	Max. Distance = 00 mtrs	N 32 ⁰ 46' 19.70''	E 74 ⁰ 51' 04.73''	do
		N1	Min. Distance = 00 mtrs	N 32 ⁰ 48' 41.94''	E 74 ⁰ 51' 16.41''	
8	North West	O1	Min. Distance= 00 mtrs	N 32 ⁰ 46' 45.79''	E 74 ⁰ 50' 42.80''	Jammu city municipal area
		P1	Max. Distance = 1794 mtrs	N 32 ⁰ 47' 56.10''	E 74 ⁰ 50' 55.93''	already developed from generations and Keran habitation.

ANNEXURE-II

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE AROUND RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY



Proposed ECO Sensitive Zone Boundary	
Actual Wildlife Sanctury Boundary	
Proposed Zoo Area Khanpur	

TABLE SHOWING GEO-COORDINATES OF BOUNDARY OF RAMNAGAR WILDLIFE SANCTUARY

S. No	Direction w.r. t	Point	Geo-Coordinates		Remarks
	boundaries of the sanctuary		Latitude	Longitude	
1	North	A	N 32 ⁰ 47' 18.37''	E 74 ⁰ 51' 57.16''	Area surrounded by
		В	N 32 ⁰ 47' 31.15''	E 74 ⁰ 52' 5.77''	Forest area of Co. 4
2	North East	С	N 32 ⁰ 47' 1.98''	E 74 ⁰ 52' 56.89''	Area surrounded by
		D	N 32 ⁰ 46' 38.87''	E 74 ⁰ 53' 25.04''	Zoo area Khanpur,
					Khanpur habitation
					& Army area

3	East	Е	N 32 ⁰ 46' 16.36''	E 74 ⁰ 52' 58.36''	Area surrounded by
_		F	N 32 ⁰ 45' 42.62''	E 74° 52' 50.98''	River Tawi & Sidhra village
4	South East	G	N 32 ⁰ 44' 52.03''	E 74 ⁰ 52' 31.55''	Area surrounded by
		Н	N 32 ⁰ 44' 37.02''	E 74 ⁰ 52' 29.65''	River Tawi & Jammu city municipal area.
5	South	I	N 32 ⁰ 45' 00.22''	E 74 ⁰ 52' 16.13''	Area surrounded by
		J	N 32 ⁰ 44' 50.42''	E 74 ⁰ 51' 47.08''	Jammu city municipal area.
6	South West	K	N 32 ⁰ 45' 20.06''	E 74 ⁰ 51' 13.26''	do
		L	N 32 ⁰ 45' 48.74''	E 74 ⁰ 51' 10.85''	
7	West	M	N 32 ⁰ 46' 19.70''	E 74 ⁰ 51' 04.73''	do
		N	N 32 ⁰ 48' 41.94''	E 74 ⁰ 51' 16.41''	
8	North West	0	N 32 ⁰ 46' 45.79''	E 74 ⁰ 50' 42.80''	Area surrounded by Jammu city municipal area already developed from generations & Keran habitation.

ANNEXURE-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

- 1. Number and date of meetings.
- 2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
- 3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
- 4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
 - [Details may be attached as Annexure]
- 5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
 - [Details may be attached as separate Annexure]
- 6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.
 - [Details may be attached as separate Annexure]
- 7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
- 8. Any other matter of importance.